(b) if so, the details thereof; and

(c) the break-up of the said package for each State?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन

2575. **श्री बरजिन्दर सिंह:**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आठवीं योजना के दौरान विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य को धनराशि आवंटित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से राज्यों ने आठवीं योजना के समाप्त हो जाने के बाद भी आवंटित धनराशि का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया; और

(ग) प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई और प्रत्येक ने कितनी धनराशि का उपयोग किया?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (ग): राज्य योजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता ब्लॉक ऋण और अनुदान के रूप में मुहैया कराई जाती है और यह विशिष्ट परियोजनाओं से संबद्ध नहीं है। राज्य के योजना परिव्यय का निर्धारण केन्द्रीय सहायता और राज्यों के अपने संसाधनों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है और योजना परिव्यय के क्षेत्रक/उपक्षेत्रक/स्कीम-वार आबंटन को राज्यों द्वारा योजना आयोग के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जाता है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों द्वारा उपयोग किए गए योजना परिव्ययों के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं। **(नीचे देखिये)**।

विवरण

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुमोदित परिव्यय / प्रत्याशित व्यय

(करोड़ रुपये)

क्र० सं०	राज्य	अनुमोदित परिव्यय (1991-92 की कीमतों पर)	प्रत्याशित व्यय*	प्रतिशत उपभोग
1.	2.	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	10500.00	12931.00 (10,006.50)	123.15 (95.30)
2.	अरूणाचल प्रदेश	1155.00	1739.20 (1,306.92)	150.58 (113.15)
3.	असम	4662.00	4980.68 (3,761.45)	106.84 (80.68)
4.	बिहार	13000.00	5507.92 (4,201.83)	42.37 (32.32)
5.	गोवा	761.00	840.64 (641.14)	110.47 (84.25)

1.	2.	3	4	5
6.	गुजरात	11500.00	11848.60 (8,962,21)	103.03 (77.93)
7.	हरियाणा	5700.00	5024.62 (3,793.51)	88.15 (66.55)
8.	हिमाचल प्रदेश	2502.00	3494.73 (2,634.51)	139.68 (105.30)
9.	जम्मू व कश्मीर	4000.00	4397.14 (3,301.95)	109.93 (82.55)
10.	कर्नाटक	12300.00	14863.36 (11,250,15)	120.84 (91.46)
11.	केरल	5460.00	7052.57 (5,249.79)	129.17 (96.15)
12.	मध्य प्रदेश	11100.00	12328.69 (9,414.14)	111.07 (84.81)
13.	महाराष्ट्र	18520.00	26129,38 (19,537,24)	141.09 (105.49)
14.	मणिपुर	979.00	1207.75 (905.19)	123.37 (92.46)
15.	मेघालय	1029.00	1087.30 (831.00)	105.67 (80.76)
16.	मिजोरम	763.00	1051.06 (796.46)	137.75 (104.38)
17.	नागालैंड	844.00	801.41 (603.11)	94.95 (71.46)
18.	उड़ीसा	1000.00	7150.30 (5,383.71)	71.50 (53.84)
19.	पंजाब	6570.00	6286.44 (4,786.30)	95.68 (72.85)
20.	राजस्थान	11500.00	12038.65 (8,983.79)	104.68 (78.12)
21.	सिक्किम	550.00	708.86 (534.87)	128,88 (97.25)
22.	तमिलनाडु	10200.00	14015.91 (10,558.47)	137.41 (103.51)

1	2	3	4	5
23.	त्रिपुरा	1130.00	1353.77 (1,027,12)	119,80 (90.90)
24.	उत्तर प्रदेश	21000.00	20001.05 (15,208.93)	95.24 (72.42)
25.	पश्चिम बंगाल	9760.00	8241.98 (6,137.84)	84.45 (62.89)
	कुल (राज्य)	175485.00	185083.01	105.47
			(139,818.11)	(79.68)

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े 1991-92 की कीमतों के आधार पर हैं।

* 1992-93 से 1995-96 के संबंध में वास्तविक व्यय और 1996-97 के संबंध में संशोधित व्यय।

Commission to study infrastructural gap in North-East

2576. SHRI KHAGEN DAS: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the previous Government appointed a one-man Commission to study the gap in infrastructure in the North-East;

(b) if so, what are the important recommendations of the Commission; and

(c) whether Government propose to implement infrastructure on the basis of the recommendations?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): (a) to (c) A High Level Commission (HLC) was set up to critically examine the backlog in respect of Basic Minimum Services and gaps in infrastructure sectors for development of States in the North Eastern Region under the Chairmanship of Shri S.P. Shukla, former Member, Planning Commission with Shri B.G. Verghese, Journalist, Shri Sainghaka, Vice-Chairman, Planning Board, Mizoram and Shri Jayanta Madhab, Chairman, North Eastern Development Finance Corporation, as Members.

As per terms of reference of the HLC, the Commission critically examined the backlog in Basic Minimum Services (BMS) and gaps in infrastructure development such as Power, Communications, Irrigation, Flood Control etc. and recommended policy initiatives and programme to bridge these gaps and rejuvenate local economy alongwith measures for institutional reforms, additional resource mobilisation and effecting public participation in development activities. The HLC also estimated total cost for providing BMS to the North Eastern States and indicative requirement of funds for infrastructure development in Ninth Five Year Plan. The recommendations of the HLC will be implemented by dovetailing the schemes with the Plans of the State Governments and Central Ministries/Departments/ Agencies.